प्रतिदिन

टेररिस्तान पाकिस्तान

जब चोर ही चोरी की गुहार लगाने लगे, तब न सिर्फ चोरी पकड़ी जाती है, वह हास्यास्पद भी बन जाता है. पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. उसे बार-बार मुंह की खानी पड़ रही है. धमकी देने वाले इस बयान पर कि उसने भारत के लिए सीमित असर वाले छोटे परमाणु बम तैयार कर रखे हैं, अभी वह लानत-मलामत झेल ही रहा था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़बोलापन दिखाकर उसने अपनी गर्दन और फंसा ली. पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उसे यूं अपमानित होना पड़ेगा. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के झूठे और अनर्गल प्रलाप की भारत ने जिस तरह पोल-पट्टी खोली, उसे सुनकर पाकिस्तानी प्रतिनिधि भी सकते में दिखे.

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह कश्मीर का पुराना राग अलापा, उससे यह तो जाहिर हुआ ही कि उसके पास कहने के लिए नया कुछ नहीं है, यह भी जाहिर हुआ कि वह किस तरह झूठ का पहाड़ खड़ा करके सहानुभूति बटोरना चाहता है. अपने देश को आतंकवाद का शिकार बताने वाले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के सारे प्रलाप को भारतीय प्रतिनिधि ने झूठ का पुलिंदा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय प्रतिनिधि एनम गंभीर ने जिस तरह मुद्दावार पाकिस्तान की परतें उधेड़ीं, उसके बाद तय है कि पाकिस्तान को अपने यहां भी आलोचना का शिकार बनना पड़ेगा. भारत की यह दो टूक बहुत दूर तक असर करेगी कि जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दिया, जो मुल्ला उमर को अब भी पाल रहा है, वह खुद को किस तरह आतंकवाद से पीड़ित बता सकता है? यूएन में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और छल-कपट की उसकी कहानियां गढ़ने की आदत की जैसी पोल खुली, उसे उसका हर पड़ोसी जान-समझ चुका है. दरअसल पाकिस्तान की यही बेबसी है, जो अब उसके सच को भी सच मानने से रोकती है.

पाकिस्तान अपने छोटे से इतिहास में विकास की अदना-सी इबारत भले न गढ़ सका हो, आतंकवाद में उसने हर दिन नई इबारत गढ़ी है. पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिस लश्कर ए तैयबा को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, उसी लश्कर का मुखिया हाफिज सईद अब पाकिस्तान में राजनीतिक दल का नेता बनने की तैयारी कर रहा है. जाहिर है, यह सब उसके पाकिस्तानी आकाओं की मिलीभगत से हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि के शब्द तल्ख थे, पर अंदाज संयत. इसमें गीदड़ भभकियों से न डरने वाले एक देश का आत्मविश्वास बोल रहा था. इस बार की चेतावनी में कुछ ढका-छिपा नहीं, शब्दों की सीधी मार थी, जब पाकिस्तान को खुले शब्दों में टेररिस्तान का नया नाम मिला, जो साबित कर रहा था कि उसके आतंक की अब कहीं और से तुलना नहीं होगी, न ही वैश्विक आतंकवाद में उसकी भूमिका को झुठलाने के हालात हैं. भारत ने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान को अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की जरूरत है. यह समझने की जरूरत है कि वह अपनी गीदड़ भभकियों में दुनिया को तबाह करने का इरादा जितनी जल्दी हो त्याग दे, क्योंकि यह न सिर्फ दुनिया के लिए तकलीफदेह है, बल्कि असह्य भी. विश्व समुदाय को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि के ये शब्द बहुत मारक थे कि, 'पाकिस्तान को अब सिर्फ यह समझाया जा सकता है कि सभ्यता, व्यवस्था, अमन के प्रति प्रतिबद्धता जताए बिना उसे साझा हितों से जुड़े राष्ट्रों के संघ में स्वीकार्यता नहीं मिल सकती.' उम्मीद है, पाकिस्तान इन शब्दों के पीछे छिपी मंशा की मजबूती को समझेगा.

पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी

एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं पेट्रोलियम मंत्री

डीजल पर टैक्स बढ़ाना किसी चक्रव्यूह में फंसने जैसा है. चक्रव्यूह से बाहर निकलना इसमें प्रवेश की तुलना में कही अधिक कठिन और महत्वपूर्ण होता है.

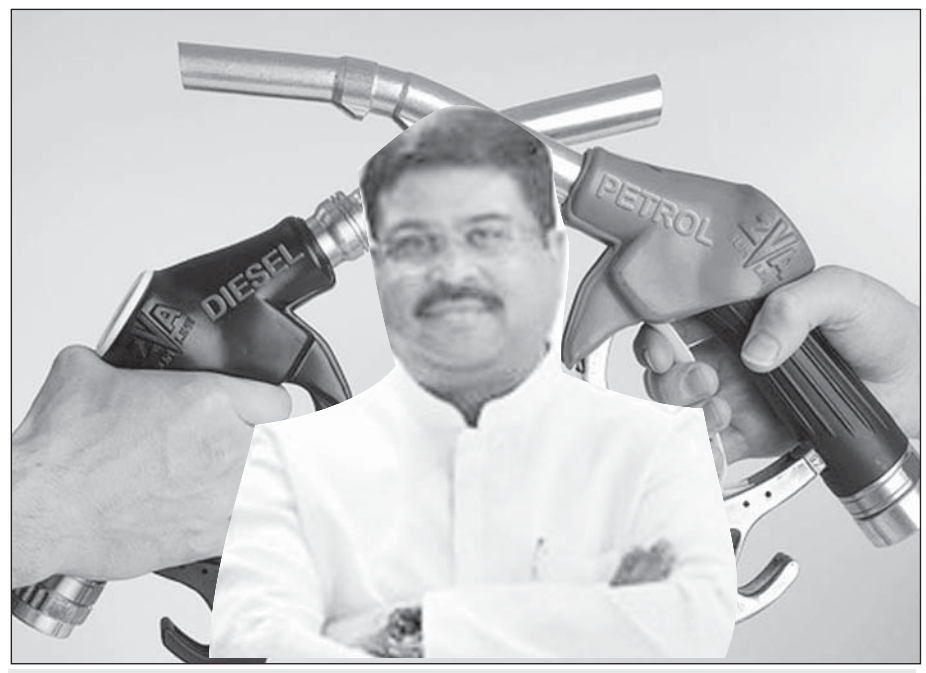

जब कच्चे तेल की कीमते नरम चल रही थी तब सरकार को चाहिए था कि तेल कंपनियों को यह सलाह देती कि वे पेट्रोलियम पदार्थो को अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम के साथ जोड़ने की बजाय लागत आधारित कीमतों का फार्मूला अपनाएं. अभी भी गिरे बेरो का कुछ नहीं बिगड़ा है. जिस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए है उससे पैदा होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचने का एक ही रास्ता है कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी भी लगाया जाए और उसके साथ ही इनकी कीमतें लागत आधारित फार्मूले से तय हों.

पेट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधान बहुत अधिक राजनीतिक दबाव में है. उन्हें पेट्रोल और डीजल के परचून मूल्यों में कमी करने को कहा जा रहा है. गौरतलब है कि इनके मूल्य उस स्तर तक ऊंचे चढ़ गए है जहां वे तीन वर्ष से कुछ अधिक पूर्व थे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते आज की तुलना में दोगुनी ऊंची थी.

प्रधान ने यह कहते हुए इन सभी दबावों का विरोध किया है कि वह परचून मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि ये मूल्य बाजार के उतार-चढाव के साथ जोड़े जा चुके हैं.

लेकिन इसके बावजूद यह बात भी कोई कम राहत पहुंचाने वाली नहीं कि प्रधान इस अवसर का लाभ उठाते हुए दृढ़ता से कह रहे है कि पेट्रोल और डीजल पर भी जीएसटी लागू किया जाए. अब देखना यह है कि सुझाव कितने व्यावहारिक है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजारो से भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमतो ने 2014 से ही नीचे सरकना शुरू कर दिया था. मई, 2014 मे प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत 107 डालर थी. लेकिन जनवरी,2016 तक यह लुढकती लुढकती 28 डालर तक आ गई थी. उसके बाद इसने फिर से उपर उठना शुरू कर दिया और सितंबर 2017 तक कीमतें 55 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी.

इसी के अनुरूप डीजल की परचून कीमते भी दिल्ली में जनवरी, 2016 में 22 प्रतिशत गिरावट दर्ज करते हुए 44.18 रुपए प्रति लिटर पर आ गई थी जबकि मई, 2014 में यह आंकडा 56.71 रुपए था. दिल्ली में पेट्रोल की कीमते भी इसी अवधि के दौरान 71.41 रुपए से 17 प्रतिशत फिसल कर 59.35 रुपए पर आ गई थी. स्पष्ट है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतो में यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतो में आई 74 प्रतिशत गिरावट की तुलना में बहुत ही कम थी.

ऐसा मुख्य रूप में इसलिए हुआ था क्योंकि केंद्र सरकार ने नरम पड़ती कच्चे तेल की कीमतो के परिप्रेक्ष्य में लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल दिया था. क्योंकि इसने मई, 2014 से लेकर जनवरी, 2016 के बीच पेट्रोल और डीजल पर 11 बार राजस्व शुल्क में वृध्दि की थी. पेट्रोल के मामले में राजस्व शुल्क में 127 प्रतिशत बढोत्तरी हुई जबकि डीजल के मामले में यह 387 प्रतिशत थी.

स्मरण रहे कि इन दोनों उत्पादों पर राज्यों द्वारा भी बिक्री कर तथा वैट लगाया जाता है और 2016-17 दौरान उन्होंने भी इन दोनों उत्पादों पर प्रादेशिक टैक्स में 16 प्रतिशत वृध्दि का 4 प्रतिशत थी. इन शुल्कों के फलस्वरूप दिल्ली प्रदेश की डीजल और पेट्रोल शुल्को से राजस्व आमदनी में 14प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई.

लेकिन अप्रैल,2017 में कच्चे तेल की कीमते उछल कर 52 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गई जो कि जनवरी,2016 की तुलना में 86 प्रतिशत अधिक थी. तब पेट्रोल और डीजल के परचून मूल्य भी बढ़ाने पड़े लेकिन यह वृध्दि क्रमशः 11 और 24 प्रतिशत थी जो कि कच्चे तेल की कीमतो में हुई बढोत्तरी की तुलना में काफी कम थी. सितम्बर, 2017 में जब कच्चे तेल की कीमते अप्रैल, 2017 की तुलना में 6 प्रतिशत और बढ़ गई तो पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भी 7 प्रतिशत की वृध्दि करनी पडी. इस अवधि दौरान टैक्सो में कोई बदलाव नहीं हुआ. वास्तव में तो इन दोनों उत्पादों पर टैक्स जनवरी, 2016 से एक ही स्तर पर टिका हुआ है.

वर्तमान बेचैनी का असली कारण जुलाई, 2014 और जनवरी, 2016 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया गया टैक्स है जिसके फलस्वरूप वैट और राजस्व कर की वसूली 2016-17 में बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गई. इसमें से केंद्र ने 2.4 लाख करोड की वसूली की जबकि शेष 1.6 लाख करोड़ की वसूली राज्यों ने की. अब चूंकि राज्यो को केंद्रीय राजस्व में 42 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल है तो पेट्रोलियम उत्पादों से उनकी कुल टैक्स वसूल 2.6 लाख करोड़ रुपए हो गई जबकि केंद्र की हिस्सेदारी सिमट कर 1.4 लाख करोड़ पर आ गई. ऐसे में यदि टैक्सों में कटौती की जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान राज्यों को होगा.

टैक्स बढ़ाने के फैसले को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया था कि सरकारो को अपने-अपने वित्तीय घाटे में कमी लाने की जरूरत है और तेल कंपनियो को भी उनके सभी उत्पादों पर बढ़ती अंडर रिकवरी के बोझ से बचाना होगा. वास्तव में वित्तीय घाटों पर लगाम कसी गई तो कई और तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी भी अपने आप नीचे आ गई. इसके साथ ही तेल के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडी 2014-15 के 76,285 करोड़ के आंकडे से लुढ़क कर 2016-17 में मात्र 22,738 करोड रह गई.

लेकिन न तो धर्मेंद्र प्रधान और न ही वित्त मंत्री अरुण जेटली यह संज्ञान ले पाए कि कच्चे तेल की कीमतों के नीचे सरकने के दौर में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाना किसी चक्रव्यूह में फंसने जैसा है. चक्रव्यूह से बाहर निकलना इसमें प्रवेश की तुलना में कही अधिक कठिन और महत्वपूर्ण होता है.

टैक्स दरें बढ़ाते समय भी प्रधान और जेतली को यह मगजपच्ची करनी चाहिए थी कि तेल कीमते अत्यधिक बढ़ जाने और जनाक्रोश भड़कने की स्थिति में उनकी रणनीति क्या होगी. बाद में हुआ भी यही. कच्चे तेल की कीमते फिर से बढ़ रही है जबकि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए टैक्स में कमी करना नाको चने चबाने जैसा है क्योंकि यह कदम उठाने से राजस्व में कमी आएगी और बजट घाटा भी बढ जाएगा.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाना ही इस स्थिति में से निकलने का एकमात्र रास्ता है लेकिन यह दीर्घकालीन समाधान ही है. जब कच्चे तेल की कीमते नरम चल रही थी तब सरकार को चाहिए था कि तेल कंपनियों को यह सलाह देती कि वे पेट्रोलियम पदार्थो को अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम के साथ जोड़ने की बजाय लागत आधारित कीमतों का फार्मूला अपनाएं. अभी भी गिरे बेरो का कुछ नहीं बिगडा है. जिस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए है उससे पैदा होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचने का एक ही रास्ता है कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी भी लगाया जाए और उसके साथ ही इनकी कीमते लागत आधारित फार्मूले से तय हों.

ए.के.भट्टाचार्य.

प्रतिदिन

बुराई की जड़

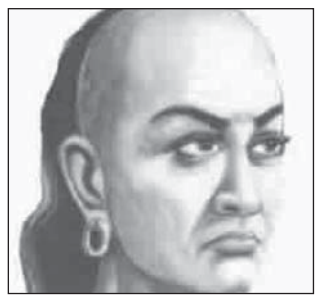

बुराई की जड़ एक बार मगध के महामंत्री चाणक्य राजकाज संबंधी परामर्श के लिए सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने जा रहे थे. रास्ते में उनके पांव में कांटा चुभ गया. उनके मुंह से चीख निकल गई. उन्होंने झुककर उस कंटीले पौधे को देखा फिर कुल्हाड़ी मंगवाई और अपने हाथों से उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया. उखाड़ कर फेंकने के बाद उन्होंने उस पौधे की जड़ों को भी जमीन से निकाला और उन्हें जला दिया. इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से छाछ मंगवाकर उसे उस स्थान पर डाल दिया ताकि पुनः पौधा पनप कर अपने काटों से किसी राहगीर को पीड़ा न पहुंचा. यह देखकर एक शिष्य जिज्ञासावश बोला-गुरुजी, आपने मात्र एक कंटीले पौधे को निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, यदि आप हमें आदेश देते तो हम तुरंत यह कर देते.

शिष्य की बात सुनकर चाणक्य मुस्करा कर बोले- मैंने तुम सबको सीख देने के लिए ही यह कार्य स्वयं किया है. इस कार्य के माध्यम से मैं तुम सब को बताना चाहता हूं कि जब तक बुराई की जड़ को खत्म न किया जाए तब तक वह पूरी तरह खत्म नहीं होती और गाहे-बगाहे अपनी चपेट में किसी न किसी को ले ही लेती है. इसलिए केवल बुराई को दूर करने की नहीं बल्कि उसकी जड़ को काटने की आवश्यकता है ताकि वह फिर कभी पनप ही न सके. यदि तुम बुराई की जड़ काट दोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सहज व शांतिपूर्ण हो जाएगा. शिष्य चाणक्य की इस बात से सहमत हो गए.

नेटीजन

महिला आरक्षण का मसला

प्रधानमंत्री मोदी के पास इतनी राजनीतिक ताकत है कि वह इस विधेयक को पारित करवा सकते हैं.

साल, 2019 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. महिला तबके को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री खास ध्यान दे रहे हैं. उज्ज्वला योजना और तीन तलाक के जरिए बीजेपी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की है. यह चर्चा भी है कि शायद चुनाव से पहले एनडीए सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आए और खटाई में पड़े इस विधेयक को पास कराने की कोशिश करे. बीजेपी के लिए यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके पास लोकसभा में बहुमत है. शायद इसे भांपते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, क्योंकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इसे पास कराने में उनकी अहम भूमिका थी. लोकसभा में यह विधेयक अटक गया था, क्योंकि यूपीए के साथी दल, खासकर सपा, राजद ने इसका विरोध किया था.

लोकसभा में इसे यूपीए ने इस डर से पहले पेश नहीं किया था कि कहीं सरकार ही खतरे में न पड़ जाए. वजह चाहे जो भी हो, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे को फिर से प्रकाश में ला दिया है. अगर यह विधेयक पारित होता है, तो इसमें उन्हें भी कुछ श्रेय मिलेगा...यह राजनीति में नया दिन जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास इतनी राजनीतिक ताकत है कि वह वर्षो से लटके इस विधेयक को पारित करवा सकते हैं.

बीबीसी में नीरजा चौधरी.

मुद्दा...

किसानी का हक मांगती महिलाएं

आने वाले दिनों की परेशानियां किसान आंदोलन को और धार देंगी. महिलाएं आंदोलनकारी तो बन ही रही हैं, उनकी मांगों को, उनके किसान होने की मान्यता को, उनके जमीन के अधिकार को अगर मुद्दा बनाया जाएगा, तो वे आंदोलन की नेता भी बनेंगी. निर्भीक और समझौता न करने वाली नेता. कभी पीछे न हटने वाली नेता.

एक बहुत बड़ी आपदा सामने खड़ी है, जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान जा रहा है. इस आपदा की शिकार लाखों गरीब, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होने वाली हैं. आपदा इस बात से पैदा होने वाली है कि इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई है. बारिश कहीं-कहीं तो बहुत अधिक हुई. पर देश के साठ फीसदी हिस्से में पानी कम गिरा है. देश में पैदा होने वाले अनाज का पचास प्रतिशत जिन राज्यों में पैदा होता है यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इनमे इस साल औसत से 39 प्रतिशत कम बारिश हुई है. महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल इस साल भी सूखाग्रस्त हैं. उनके लिए सूखे का यह तीसरा साल है.

पिछले कुछ महीनों से कई राज्यों के किसान संघर्ष करते दिख रहे हैं. हर जगह मांगें वही हैं फसलों का वाजिब दाम दो और कर्ज माफ करो. सरकारें इन मांगों को अनसुनी कर रही हैं और अपने मनपसंद बुद्धजीवियों-विशेषज्ञों द्वारा लेख लिखवा रही हैं कि यदि ये मांगें मान ली जाएं, तो देश दिवालिया हो जाएगा.

आंदोलकारी किसानों में महिलाओं की संख्या कम नहीं हैं. ये महिलाएं घर का सारा काम करके आंदोलन में शामिल हो जाती हैं. ये दिन भर नारे लगाती हैं, फिर थकी-हारी घर जाती हैं. ये महिलाएं भी किसान हैं. पर उनको किसान कोई मानता नहीं है. ये महिलाएं खेतों में मजदूरी का काम करती हैं, अपने परिवार की जमीन पर खेती का काम करती हैं और अपने खेतों की देख-रेख भी करती हैं. ग्रामीण क्षेत्र से पुरुषों का पलायन बढ़ रहा है और उनकी जगह घर की महिलाएं ले रही हैं. ग्रामीण महिलाएं कृषि से जुड़े 85 प्रतिशत विभिन्न काम करती हैं. 20 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों की मुखिया भी महिला हैं.

पशुओं को चारा देना, उनका दूध निकालना और दूध बेचना औरतों के काम हैं. पर उन्हें किसान या पशुपालक का दर्जा नहीं मिलता. वे खेत और जमीन की मालिक भी नहीं बन पातीं. लंबी लड़ाइयों के बाद कुछ कानूनी अधिकार उन्हें मिले भी, तो उनका फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है. दो ही राज्यों पश्चिम बंगाल और अविभाजित आंध्र प्रदेश में जमीन के संयुक्त पट्टे बांटे गए थे. महिलाएं चूंकि किसान नहीं मानी जातीं, इसलिए उन्हें न तो किसान पत्र मिल पाता है, न ही बैंक से कर्ज. इसीलिए किसानों के संघर्ष में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. कहीं-कहीं उनके अधिकारों की मांग भी उठने लगी है. जिस सूखे की चपेट की बात अब सरकार करने लगी है, उसका इन ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर सुनामी जैसा असर पड़ने वाला है. पुरुषों के पलायन के साथ महिलाओं का पलायन भी बढ़ेगा.

सुभाषिनी सहगल अली.

इंटरनेशनल मीडिया

इशाक डार से आगे

ऐसे समय में, जब वित्त मंत्री इशाक डार को नवाज शरीफ के साथ-साथ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह स्वाभाविक है कि वाले दिनों में उन्हें मुश्किल सवालों से टकराना पड़ेगा. हालांकि इधर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह निष्कर्ष गलत न होगा कि वह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की कार्रवाई को राजनीति प्रेरित और बदले का मामला कहें. मरियम नवाज के इस मामले को इसी रूप में देखने के बाद कोई कारण नहीं है कि डार उनकी बात से नाइत्तफाकी रखें. राजनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो, एक बात साफ है कि इशाक डार को अब वित्त मंत्री पद तो छोड़ना ही होगा. महज इसलिए नहीं कि वह कानूनी दांवपेच में उलझे हैं, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनमें यह स्वीकार करने की क्षमता है कि देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर है और तत्काल सुधार न हुआ, तो देश जल्द ही बड़े आर्थिक संकट में फंस जाएगा.

डार आर्थिक मोर्चे पर खुद को सफल मानते हैं. कुछ मामलों में वे सफल रहे भी हैं, मगर आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ उतना उजला भी नहीं है. सच यही है कि पाकिस्तान को तत्काल एक ऐसे भविष्योन्मुखी वित्त मंत्री की जरूरत है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करे. बीते चार वर्षो में अर्थव्यवस्था में दिखा बदलाव अब अलग-अलग मोर्चो पर उतार पर है. चालू खाते का घाटा बढ़ता गया है, मुद्रा भंडारण में गिरावट आई है. अर्थव्यवस्था बिगाड़ने वाली संरचनात्मक बाधाएं दूर नहीं की गईं. अब समय वास्तविकता को समझने और उसके अनुकूल आचरण करने का है. देश को अब एक ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत है, जो अपने बचे हुए छोटे से कार्यकाल में भी अर्थव्यवस्था के नीचे जाने के कारणों की पहचान करके इसे गति देने वाली दीर्घावधि की कार्ययोजना दे सके. संक्षेप में, देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, जो नीतिगत बाध्यताओं के साथ चलते हुए, धीरे-धीरे आर्थिक समायोजन की दिशा में आगे बढ़े. जरूरत हो, तो कुछ दिनों के लिए विकास की कीमत पर भी. अब यह तय हो चुका है कि कम से कम डार तो वह इंसान नहीं ही हैं. सो, उन्हें अब अपना पद छोड़ ही देना चाहिए.

डॉन, पाकिस्तान.

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH
DAWN

आपकी बात

सरकार के लाडले

करीब 18 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को चार प्रतिशत बढ़ा मंहगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय फड़णवीस सरकार ने लिया है, जो 1 जनवरी से लागू किया जाने वाला है. लेकिन उन किसानों और खेत मजदूरों का क्या, जो दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत कर देश की भूख भगाते हैं? दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी हैं, जो बार-बार मंहगाई भत्ता दिये जाने के बाद भी 100-200 की रिश्वत लेते भी पकड़े जाते हैं.मंहगाई की आग में तो सबसे ज्यादा आमलोगों के साथ ही गरीब लोग झुलसते हैं. कभी किसी सरकारी कर्मचारी को आत्महत्या करते देखा है (सिवा इसके जब किसी बड़े घपले में गर्दन फंस जाए)? साल में इनके काम के दिन भी कितने हैं, और जो हैं उसमें भी ये कितना काम करते हैं? दूसरी ओर बिना किसी आसरे रहते हुए दिन-रात पिसते रहने वाले मेहनतकशों का क्या? दूसरी तरफ कम से कम बीस हजार वेतन पाने वाले 'बेचारों' को बढ़ा मंहगाई भत्ता दिया जाता है.

मंगेश मोरे,अमरावती.

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com
'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.